



दलहन में भारत का आत्मनिर्भरता मिशन

2030-31 तक दालों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की छह-वर्षीय योजना

11 अक्टूबर, 2026

आयात पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर

भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है; दालें दुनिया भर में महत्वपूर्ण और प्रोटीन से भरपूर खाद्य फसलें हैं। दालों में 20-25% प्रोटीन होता है, जो गेहूं से दोगुने से भी ज्यादा और चावल से लगभग तीन गुना ज्यादा है। दालें भारत के कृषि निर्यात में अहम भूमिका निभाती हैं और भारतीय आहार का एक ज़रूरी हिस्सा बनी हुई हैं, जिससे पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसी महत्व को समझते हुए, सरकार ने 11 अक्टूबर, 2025 को 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया। 11 अक्टूबर को जब राष्ट्र इस मिशन की शुरुआत की पहली वर्षगांठ मना रहा है, तब यह महत्वपूर्ण पहल अपनी रफ़्तार से बढ़ रही है। इस मिशन के लिए 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 11,440 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह एक व्यापक मूल्य-श्रृंखला दृष्टिकोण के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

स्पष्ट लक्ष्य वाला एक मिशन

इस मिशन के तहत, 2030-31 तक उत्पादन के लगभग 350 लाख टन तक पहुँचने और प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़कर 1,130 किलोग्राम होने की उम्मीद है। इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने वाले मुख्य रणनीतिक उपाय इस प्रकार हैं:

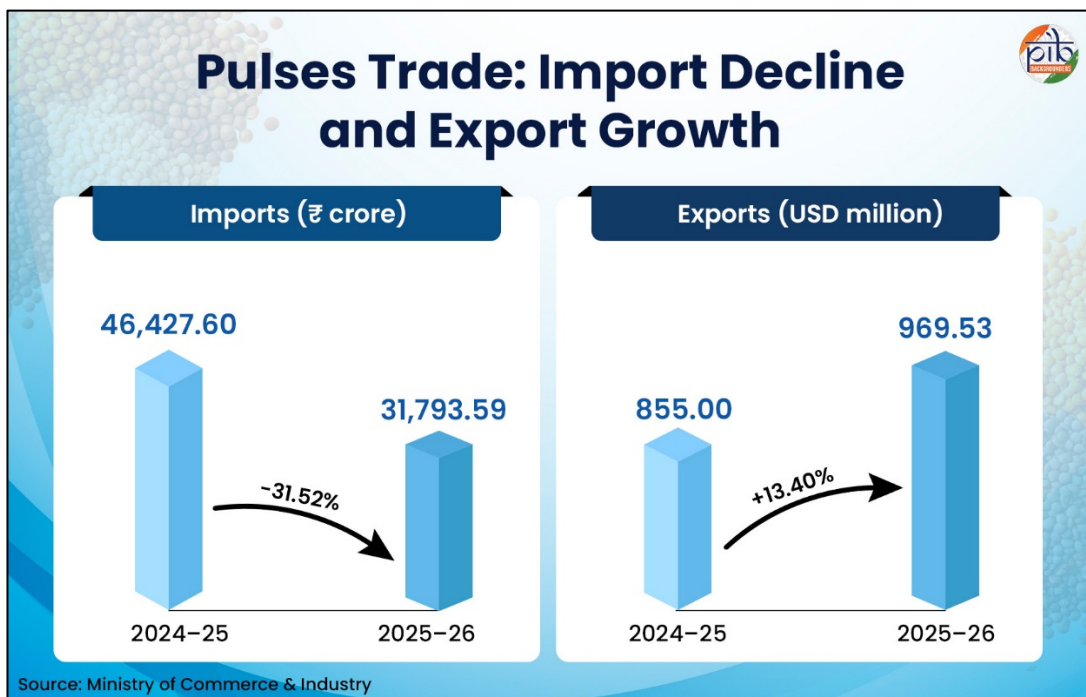
- तूर (अरहर), उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना
- जलवायु-अनुकूल बीजों और बीजों की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देना
- छह वर्षों में 87.5 लाख मुफ्त बीज किटों और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण

- 2030-31 तक 310 लाख हेक्टेयर के कुल लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दलहन की खेती के दायरे को 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना।
- उत्पादन बढ़ाने के लिए 489 ज़िलों को शामिल करते हुए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण
- 1,000 प्रसंस्करण इकाइयों (दाल मिलों) की स्थापना
- इच्छुक और पंजीकृत किसानों से एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से तूर, उड़द और मसूर की सुनिश्चित खरीद
- आयात पर निर्भरता कम होने और विदेशी मुद्रा की बचत होने की उम्मीद

भारत का प्रमुख दाल उत्पादन केंद्र

वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के दलहन क्षेत्र ने घरेलू उत्पादन, कृषि रकबे और फसल की उपज में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कृषि में निरंतर हो रही प्रगति और मजबूत स्थानीय उत्पादन देश की दलहन अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं।

- भारत का कुल दाल उत्पादन 2024-25 में 256.83 लाख टन से बढ़कर 2025-26 में 274.09 लाख टन (तृतीय अग्रिम अनुमान) हो गया।
- भारत में दलहन की खेती का रकबा 2024-25 में 277.20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 286.46 लाख हेक्टेयर हो गया।
- दलहन उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर दालों की उत्पादकता में सुधार हुआ, क्योंकि कुल पैदावार 2024-25 के 926 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई।

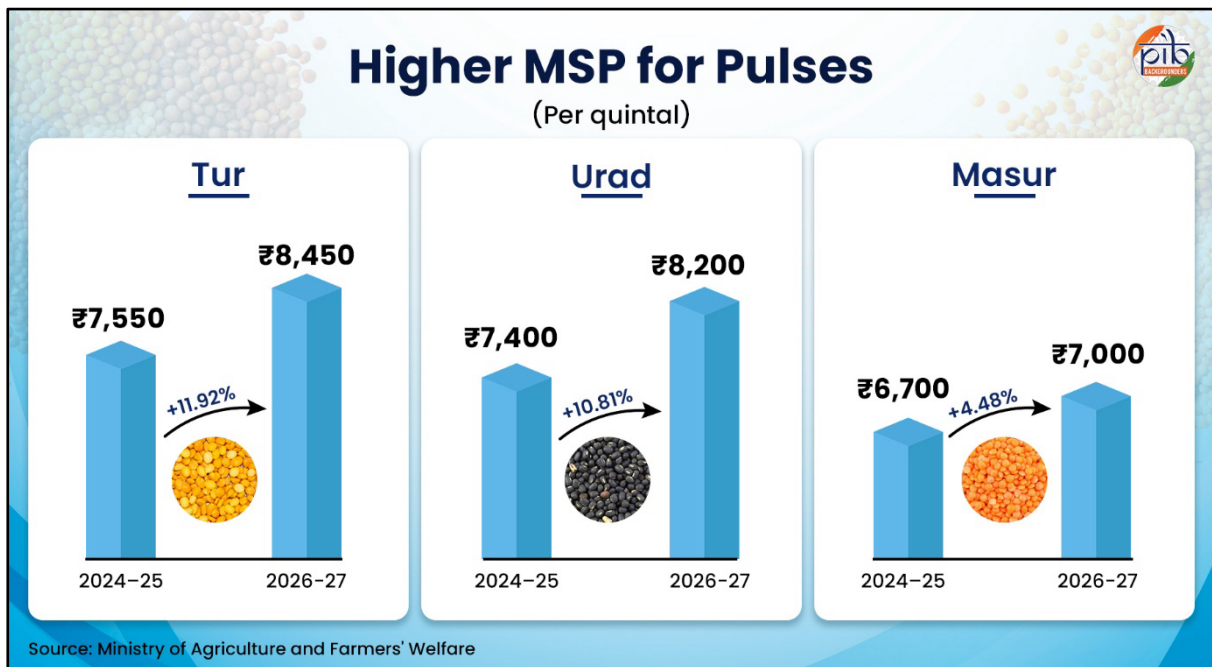


- भारत में दालों का आयात 31.52% घटकर 2024-25 में 46,427.60 करोड़ रुपये से 2025-26 में 31,793.59 करोड़ रुपये हो गया।
- भारत से दालों का निर्यात 13.40% बढ़कर 2024-25 में 855 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 969.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2025-26 के दौरान कुल निर्यात 10.01 लाख टन तक पहुंच गया।
- 2025-26 में, निर्यात के प्रमुख देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, अमेरिका और श्रीलंका शामिल थे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी और सुनिश्चित खरीद

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में पर्याप्त वृद्धि करके दाल की खेती करने वाले किसानों के लिए मूल्य सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रही है। समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को सही दाम मिलते हैं और दाल की मुख्य फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।

- विपणन सत्र 2024-25 के लिए उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 7,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था, जिसे 800 रुपये (10.81%) बढ़ाकर 2026-27 के लिए 8,200 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।
- वर्ष 2024-25 के लिए तूर (अरहर) का एमएसपी 7,550 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसमें 900 रुपये (11.92%) की वृद्धि हुई और यह 2026-27 में 8,450 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया।
- वर्ष 2024-25 के लिए मसूर का एमएसपी 6,700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जिसे 2026-27 के लिए 300 रुपये (4.48%) बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।



मिशन के तहत, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) को चार साल (2025-26 से 2028-29) की अवधि के लिए

तूर, मसूर और उड़द की 100% खरीद के लिए अधिकृत किया गया है। 17 जून 2026 तक, एनसीसीएफ दाल खरीद डैशबोर्ड से मिली मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- एनसीसीएफ ने 9 राज्यों में कुल **10.55 लाख** टन दालों की खरीद की। किसानों को सीधे कुल **7,047 करोड़ रुपये** मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भुगतान जारी किया गया। इस पहल से कुल **7.74 लाख पंजीकृत** किसानों में से **4.69 लाख** किसानों को फायदा हुआ।
- खरीफ 2025-26 के तहत, **6,431 करोड़ रुपये** मूल्य की **7.89 लाख टन दालों** की खरीद की गई, जिससे **3.66 लाख किसान** लाभान्वित हुए।
- रबी 2026-27 के तहत, दालों की खरीद **23.51 लाख टन** तक पहुँच गई, जिसके तहत **14,217 करोड़ रुपये का एमएसपी** जारी किया गया और इससे **10.20 लाख** किसान लाभान्वित हुए।
- दालों की खरीद **2024-25 के 18,39,504.77 टन** से बढ़कर 2025-26 में **31,40,883.92 टन** हो गई।

मिशन की शुरुआती प्रमुख प्रगति

मिशन की शुरुआती प्रगति अवसंरचना निर्माण और किसानों को सहायता देने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने को दर्शाती है। अब तक की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- मिशन के तहत **1,000 दाल प्रसंस्करण इकाइयां** स्थापित करने की योजना है, जिनमें से पहले चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **528 इकाइयाँ** पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के सृजन एवं विस्तार (सीईएफपीपीसी) के लिए कुल **23 दाल प्रसंस्करण इकाइयों** को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं में से **18 दाल प्रसंस्करण इकाइयों** का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।
- धान की फसल के बाद दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, मिशन का लक्ष्य छह वर्षों में **87.5 लाख बीज किट** वितरित करना है, जिसमें से **9.25 लाख किट** रबी 2025-26 के दौरान वितरित किए गए हैं।

डिजिटल निगरानी एवं बीज का पता लगाने की क्षमता

सरकार सभी स्तरों पर निर्बाध निगरानी, वास्तविक समय निरीक्षण और लक्षित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है:

- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना, कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए एक **त्रि-स्तरीय संचालन समिति** नेटवर्क बनाया गया है।
- 'कृषि मैपर' एप्लिकेशन बीज किस्मों के प्रदर्शन और उपज की सटीक जियो-फेंसिंग, भूमि की जियो-टैगिंग और वास्तविक समूह पर निगरानी को सक्षम बनाता है।
- 'साथी' (सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसिबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री) पोर्टल बीज के पूरे जीवन चक्र को शामिल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह उपाय बीज उत्पादन से लेकर

प्रमाणन और बीज की बिक्री तक, बीज आपूर्ति श्रृंखला के स्वचालन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

- **एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण:** लक्षित पोषक तत्व वितरण और सटीक फसल पूर्वानुमान सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत किसान आईडी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड विश्लेषण और सत्यापित भूखंड सर्वेक्षणों के साथ जोड़ता है।
- **'ई-समृद्धि' और 'विस्तार'** जैसे सत्यापन प्लेटफॉर्म सीधे भुगतान, रीयल-टाइम बाज़ार डेटा और घरेलू मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

आज की बुआई, कल की सुरक्षा

शुरुआती रुझान बताते हैं कि **दलहन के मामले में 'आत्मनिर्भरता मिशन'** नीतिगत इरादे और जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन के बीच सफलतापूर्वक तालमेल बिठा रहा है। गारंटीकृत मूल्य समर्थन ने उत्पादकों के विश्वास को पुनर्स्थापित किया है, जबकि 'साथी' और 'ई-समृद्धि' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। जैसे-जैसे भारत **2030-31 तक 350 लाख टन उत्पादन** के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, यह एकीकृत मूल्य-श्रृंखला ढांचा न केवल दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्रोटीन सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत का वादा करता है, बल्कि पूरे व्यापक कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी पेश करता है।

संदर्भ

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177847®=48&lang=2>

<https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-09/Strategies-and-Pathways-for-Accelerating-Growth-in-Pulses-towards-the-Goal-of-Atmanirbharta.pdf>

<https://www.ibef.org/news/union-cabinet-approves-mission-for-aatmanirbharta-in-pulses-with-rs-11-440-crore-us-1-24-billion-outlay-to-achieve-self-sufficiency-by-2030-31>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284230®=48&lang=1>

<https://upag.gov.in/dash-reports/progressivecropareasown>

<https://apeda.gov.in/Pulses>

<https://pulsesmission.da.gov.in/pulseswebinar.aspx>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2239790®=48&lang=2>

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/union-cabinet-approves-mission-for-aatmanirbharta-in-pulses-for-2025-26-to-2030-31/

पीआईबी बैकग्राउंडर्स

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=155497&ModuleId=3®=48&lang=1>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/आरटी/एसके